



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 579]  
No. 579]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 8, 2005/ज्येष्ठ 18, 1927  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 8, 2005/JYAISTHA 18, 1927

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 जून, 2005

का.आ. 790(अ).— जबकि विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) (यहां इसके बाद अधिनियम के रूप में उल्लिखित) दिनांक 10 जून, 2003 को लागू हुआ ;

और जबकि अधिनियम की धारा 50 यह व्यवस्था करती है कि राज्य आयोग विद्युत प्रभार की वसूली, विद्युत प्रभार की बिलिंग के लिए अंतराल, उसका भुगतान न करने पर विद्युत की आपूर्ति रोकने, विद्युत आपूर्ति बहाल करने, विद्युत संयंत्र, विद्युत की लाईन अथवा मीटर से छेड़छाड़ करने, खतरे में डालने अथवा क्षति पहुंचाने, आपूर्ति काटने और मीटर हटाने के लिए वितरण लाइसेंसधारी अथवा उसकी ओर से कार्यरत किसी व्यक्ति के प्रवेश, विद्युत लाइनों अथवा विद्युत संयंत्र या मीटर प्रतिस्थापित करने, बदलने अथवा रख-रखाव करने के लिए प्रवेश हेतु व्यवस्था करने के लिए विद्युत आपूर्ति संहिता निर्दिष्ट करेगा ;

और जबकि वितरण लाइसेंसधारियों ने विद्युत की चोरी पर नियंत्रण करने और इस संबंध में उपर्युक्त कार्रवाई करने में कठिनाइयां व्यक्त की हैं ;

और जबकि वितरण लाइसेंसधारियों को बिजली की चोरी अथवा विपथन के मामले में सामयिक और उपर्युक्त कार्रवाई करने के लिए समर्थ बनाना विद्युत उद्योग के विकास और सभी क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो गया है ;

और जबकि विद्युत उद्योग के विकास और सभी क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति करने में सहायक उपाय करना अधिनियम की अन्य बातों जैसा उसके प्रस्तावना में यथावर्णित है, में से उद्देश्य हैं;

और जबकि वितरण लाइसेंसधारी द्वारा विद्युत की चोरी पर नियंत्रण करने में अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं ;

अब, इसलिए केन्द्र सरकार अधिनियम की धारा 183 द्वारा सौंपी गई अपनी शक्तियों के प्रयोग में कठिनाइयां दूर करने के लिए अधिनियम के उपबंधों के असंगत नहीं, अधिनियम की धारा 50 के अनुसार विद्युत आपूर्ति संहिता के संबंध में एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः —

**1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :**

- (1) इस आदेश को विद्युत (कठिनाइयां हटाना) आदेश, 2005 कहा जा सकता है।
- (2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

**2. विद्युत आपूर्ति संहिता में विद्युत की चोरी पर नियंत्रण करने के लिए उपायों को शामिल करना :**

- (1) अधिनियम की धारा 50 के अधीन राज्य आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट विद्युत आपूर्ति संहिता में निम्नलिखित भी शामिल होंगे नामतः :-
  - (i) उपयुक्त न्यायालय द्वारा अधिनिर्णयन होने तक विद्युत की चोरी के मामले में देय विद्युत प्रभार के आकलन की विधि ;
  - (ii) विद्युत की चोरी अथवा अनधिकृत प्रयोग के मामले में विद्युत की आपूर्ति विच्छेदित करना और मीटर, विद्युत लाईन, विद्युत संयंत्र और अन्य उपकरण हटाना ; और
  - (iii) विद्युत की विपथन, चोरी अथवा विद्युत के अनधिकृत प्रयोग अथवा विद्युत संयंत्र, विद्युत लाईन अथवा मीटर से छेड़छाड़ करने, खतरे में डालने अथवा क्षति पहुंचाने को रोकने के लिए उपाय।
- (2) विद्युत आपूर्ति संहिता में उपर्युक्त उपबंध अधिनियम अथवा अन्य लागू कानून के अधीन लाइसेंसधारी की परिसंपत्तियों अथवा हितों के संरक्षण के लिए तथा देय राशि वसूल करने के लिए लाइसेंसधारी के अन्य अधिकारों को प्रभावित किये बिना होंगे।

[फा.सं. 23/54/2004-आर एंड आर]

अजय शंकर, अपर सचिव

**MINISTRY OF POWER****ORDER**

New Delhi, the 8th June, 2005

**S.O. 790(E).**—Whereas the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) (hereinafter referred to as the Act) came into force on the 10th June, 2003;

And whereas section 50 of the Act provides that the State Commission shall specify an Electricity Supply Code to provide for recovery of electricity charges, intervals for billing of electricity charges, disconnection of supply of electricity for non-payment thereof, restoration of supply of electricity, tampering, distress or damage to electrical plant, electric lines or meter, entry of distribution licensee or any person acting on his behalf for disconnecting supply and removing the meter, entry for replacing, altering or maintaining electric lines or electrical plant or meter;

And whereas the distribution licensees have expressed difficulties in controlling theft of electricity and in taking appropriate action in this regard;

And whereas enabling the distribution licensees for taking timely and appropriate action in cases of theft or diversion of electricity has become necessary for the development of electricity industry and ensuring supply of electricity to all areas;

And whereas taking measures conducive to development of electricity industry and supply of electricity to all areas are objectives, amongst others, of the Act, as stated in its preamble;

And whereas the difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the Act in controlling theft of electricity by the distribution licensees;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of its powers conferred by section 183 of the Act hereby makes the following order in respect of electricity supply code in terms of section 50 of the Act, not inconsistent with the provisions of the Act, to remove the difficulties, namely. —

1. Short title and commencement.—

(1) This order may be called the Electricity (Removal of Difficulties) order, 2005.

(2) It shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. Inclusions of measures to control theft in Electricity Supply Code. -

(1) The Electricity Supply Code as specified by the State Commission under section 50 of the Act shall also include the following, namely:-

- (i) method of assessment of the electricity charges payable in case of theft of electricity pending adjudication by the appropriate court;
- (ii) disconnection of supply of electricity and removing the meter, electric line, electric plant and other apparatus in case of theft or unauthorized use of electricity; and
- (iii) measures to prevent diversion of electricity, theft or unauthorized use of electricity or tampering, distress or damage to electrical plant, electric lines or meter.

(2) The above provisions in the Electricity Supply Code shall be without prejudice to other rights of the licensee under the Act or any other applicable laws to recover the sum due and to protect the assets and interests of the licensee.

[F. No. 23/54/2004-R & R]  
AJAY SHANKAR, Addl. Secy.